आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 29.05.2023 से 04.06.2023)

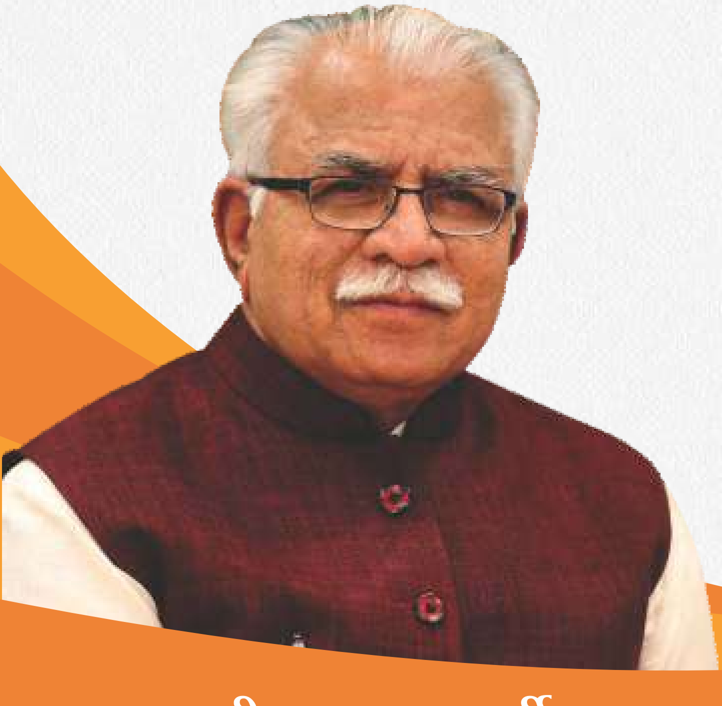

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर

(दिनांक 29.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर महा संपर्क अभियान के तहत अयोजित कार्यक्रम में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हर देशवासी के कल्याण के लिए कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को पुनरू विश्व गुरु बनाने के लिए दुनिया में विभिन्न देशों का दौरा कर भारत की संस्कृति और विरासत की जो झलक दिखाई है, उससे हर भारतीय को गौरव की अनुभूति हुई है। आज वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान बनी है, उससे जनता को भी लाभ हो रहा है। दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के बढ़ते कद को देखकर अब तो बड़े देशों के नेता भी कहने लगे हैं कि मोदी इज दी बॉस।

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक राजनीतिज्ञ की बजाय एक स्टेट्समैन हैं, जो भविष्य की सोचते हैं। उन्होंने भारत की सदियों पुरानी विरासत योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है।

कई सालों तक उन्होंने साथ में काम किया है। उन्होंने हमेशा देश की जनता के कल्याण, देश की सांस्कृतिक पहचान और देश के भविष्य के बारे में सोचा है। वर्ष 2015 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी सोच का एक उदाहरण है और समाज के सहयोग से इस अभियान में अपार सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया मन की बात कार्यक्रम भी इसी का एक ओर उदाहरण है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, बल्कि वे देशभर के सामाजिक विषयों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर बात करते हैं। इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड हो चुके हैं, जो अपने

आप में एक रिकॉर्ड है।

माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने सदैव कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय उत्थान के साथ–साथ 5एस–शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर काम कर रही है। शिक्षा के नाते से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को देश में लागू किया है, जिसका

उद्देश्य प्राचीन पद्धति को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाते हुए बच्चों में देश के प्रति भाव जागृत करना है।

एनआईसीडीआईटी की शीर्ष मॉनिटरिंग ऑथोरिटी की दूसरी बैठक

(दिनांक 30.05.2023)

प्रभाव : माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की शीर्ष मॉनिटरिंग ऑथोरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाईस चेयरमैन श्री सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल

चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून माह तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इंटर्नल रेल यार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के साथ–साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है।

इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा

होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में भी सक्षम होंगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी) से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं।

प्रशासनिक सचिवों के साथ 100 करोड़ से अधिक के प्रॉजेक्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक

(दिनांक 30.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना व लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजैक्ट को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 5 जून को विभिन्न मुद्दों पर अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कसाऊ बांध का निर्माण करना, दादुपुर से हमीदा हैड न्यू लिंक चौनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना, एसवाईएल नहर के पानी को वाया हिमाचल प्रदेश लाने, बिजली पर सैस लगाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी की निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार

करें, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। राज्य के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए पेयजल एंव सिंचाई की कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोका जाएगा। इससे अलावा गुरूग्राम मेवात फीडर कैनाल, जेएलएन फीडर की क्षमता बढाने, हांसी ब्रांच की क्षमता बढाने के कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सिंचाई एवं जल परियोजनाओं से भूजल संकट वाले क्षेत्रों में निजात मिलेगी और इण्डस्ट्री और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यमुनानगर में डब्लूजेसी कैनाल की रिमोडलिंग, करनाल में मुनक हैड से खुबडु तक कंक्रीट लिंक, गुरूग्राम वाटर सर्विस चौनल की रिमोडलिंग, गुरूग्राम के धनवापुर व बहरमपुर में एसटीपी की क्षमता बढाना, फतेहाबाद के गोरखपुर वाटर कन्वेंस सिस्टम का विकास

साप्ताहिक सूचना पत्र

करना, झज्जर में जुआ ड्रेन के निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की राशि से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम व फरीदाबाद का बेहतरीन नेटवर्क बनाने के लिए मेट्रो रेल एवं सड़क तन्त्र को मजबूत करना सरकार का प्रयास है। इस रूट पर मेट्रो रेल व फास्ट रेल गाड़ियां चले। इसके लिए गुरूग्राम में 28 किलोमीटर के मेट्रो रेल नेटवर्क पर जीएमडीए एक माह में सिविल कार्य शुरू करेगा।

रेजांगला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक मेट्रो रेल कनैक्टिविटी, सराय कलेखां से पानीपत तक रिजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट हेतू धनवापुर में 100 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा चंदु बुढेडा में 100 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जून माह में शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद के प्रतापगढ व मिर्जापुर में बनाए जाने वाले एसटीपी का 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, फरीदाबाद रोड़ से एनएच–48 गुरूग्राम तक 845.54 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पेरिफेरल रोड़ का निर्माण किया जाएगा। गुरूग्राम में श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं होस्पीटल का निर्माण कार्य आगामी तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा।

बैठक में अवगत करवाया गया कि जीन्द मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण खरीदने की प्रक्रिया जारी है। गुरूग्राम में सैक्टर 58 से 115 तक 226.31 करोड़ रुपए की लागत से 113 किलोमीटर लम्बाई की पेजयल पाईप लाईन डाली जा रही है। इसके बन जाने से सैक्टर 71 से 81 में रहने वाले नागरिकों को बेहतर पेयजल सुलभ होगा। वाटिका चौक सोहना रोड़ पर मास्टर ड्रेन का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैक्टर 78 फरीदाबाद में देश का एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेशन सेंटर बनाया जा

साप्ताहिक सूचना पत्र

रहा है। इसमें 200 कमरों का होटल, प्रदर्शनी व ऑडिटोरियम ब्लॉक भी बनाया जाएगा। इससे फरीदाबाद में आवागमन बढेगा और जेवर एयरपोर्ट की कनैक्टिविटी भी बढेगी।

एनएच 21ए फोरलेन पिंजौर बाईपास की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएमजी प्रोजैक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए रेलवे अधिकारियों से बातचीत करें। रेवाड़ी–नारनौल, रेवाड़ी–झज्जर वाया दादरी लिंक रोड़ का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इस पर तीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा सड़क मार्ग में यमुना नहर पुल बनाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन विभागों की लगभग 37927 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इनमें से लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं केवल फरीदाबाद व गुरूग्राम के विकस की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्यो में तेजी लाएं और लगातार मोनिटरिंग भी सुनिश्चित करें।

किसानों को 181 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी

(दिनांक 31.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के किसानों से किया अपना वादा निभाते हुए और उन्हे बड़ी राहत देने के लिए आज गत मार्च व अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि एक क्लिक से ई–क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी।

उन्होंने कहा कि हमने किसान की फसलों को हुए नुकसान का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी। आज गेहूं, सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों का शत–प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वर्तमान राज्य सरकार ने ई–गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले।

उन्होंने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए किसान के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाती है ।

इसके लिए मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है ।

संत कबीर कुटीर से नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को किया रवाना

(दिनांक 31.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को संत कबीर कुटीर, चंडीगढ़ से झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि हमें प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के साथ–साथ नशे से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है। ताकि लोग खुद तो इससे बचें ही साथ ही दूसरे लोगों को भी इसके सेवन से राकें।माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है और इन्हें आगे बढकर कार्य करना चाहिए। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए और पानी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनसंदेश रथ यात्रा निकाली जा

रही है। यह लोगों को जागरूक करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से यह यात्रा गुजरेगी वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस नशे जैसी बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए सभी को इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए।

इस मिशन के संयोजक बाल योगी महंत चरण दास महाराज जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में उनकी यह जन संदेश रथ यात्रा नशा, पानी और पर्यावरण की जागरूकता को लेकर शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। युवा मंडलों, ग्राम पंचायतों ,धार्मिक एवं शिक्षण संस्थानों तक उनका संदेश पहुंचेगा, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके।

जनसंदेश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल योगी महंत चरण दास महाराज और यात्रा का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक

(दिनांक 01.06.2023)

प्रभाव : पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी की अध्यक्षता में आज माननीय मुख्यमंत्री और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई। माननीय चंडीगढ़ के प्रशासक जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उन पर आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए और हरियाणा के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विषय बड़ा विषय नहीं है, यह करना संभव है। हरियाणा, पंजाब के इस सहयोग से निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत होगी। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में

हरियाणा राज्य का हिस्सा दिया गया था और हरियाणा के कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज के युग में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से भी राज्यों के कॉलेजों की संबद्धता हो रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें और सभी राज्यों का आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों। इसलिए हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से की जाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें हरियाणा के कॉलेज का भी एफिलिएशन होना चाहिए। केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध बने और उसकी अवश्यकताएं भी पूरी हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं।

बैठक में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन विषयों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय मांगा।

सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक

(दिनांक 01.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक कर कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों द्वारा लिखित में प्राप्त शिकायतों, मांगों व सुझावों को आधिकारी गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। प्रदेशवासियों को किसी भी समस्या व शिकायतों के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसी उद्देश्य के लिए ही जन संवाद कार्यक्रम के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है। सरकार का ध्येय हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है। उनकी शिकायतों व मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इसलिए अधिकारी हर 7 दिन में जन संवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग–अलग श्रेणियां बनाई जाएं, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए ई– गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं और जन संवाद पोर्टल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक जन संवाद

पोर्टल पर लगभग 7200 शिकायतें व मांगों को दर्ज किया जा चुका है और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह बताया है कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई–कई कॉपी भिन्न भिन्न जन प्रतिनिधियों को देते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए हमने उनकी हर समस्या को जानने के लिए जन संवाद पोर्टल के रूप में नया सिस्टम बनाया है।

इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन संवाद पोर्टल के माध्यम से गांव स्तर तक किये जाने वाले कार्यों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। इस पोर्टल की मुख्यमंत्री कार्यालय में दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, सभी नोडल अधिकारी भी इस पोर्टल को रोजाना देखेंगे और आवश्यक कार्रवाई कर स्टेटस अपडेट करेंगे।

इस प्रकार से अब सीएम ऑफिस से लेकर ग्राम स्तर तक हर कार्या की मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, सीएम विंडो और जन संवाद पोर्टल को हर प्रशासनिक सचिव या उनके नोडल अधिकारी दैनिक आधार पर देखें, ताकि कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा सके।

गुरुग्राम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को लेकर अहम बैठक

(दिनांक 02.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज रिमोडलिंग ऑफ गुरूग्राम वाटर सप्लाई के डिजाईन की अनुमति को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि गुरूग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे गुरूग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना भी तैयार की गई है। इन परियोजनाओं पर 2267 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना के कन्सेप्ट को लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर विस्तार से चर्चा की गई। लगभग 1517 करोड़ रुपए की गुरूग्राम वाटर सप्लाई परियोजना गुरूग्राम, मानेसर व बहादुरगढ की वर्ष 2050 की आबादी को फोकस रखकर तैयार की गई है। उस समय इन शहरों को लगभग 1504 क्यूसिक पानी की आवश्यकता होगी। गुरूग्राम वाटर सप्लाई परियोजना का करोई से आरम्भ

होगी और बसई में सम्पन्न होगी। लगभग 69 किलोमीटर लम्बी वाटर सप्लाई को पूर्ण रूप से कवर करके ले जाया जाएगा जिसमें माईल्ड स्टील पाईप का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को मई 2026 में पूरा कर लिया जाएगा।

मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को भी मेवात की आबादी वर्ष 2050 को मध्येनजर रखकर बनाया गया है। इसके माध्यम से लगभग 390 क्यूसिक पानी की आवश्यकता होगी और 150 से अधिक गांवों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ होगा। मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। मेवात फीडर पाईप लाईन परियोजना तैयार कर विभाग द्वारा फरवरी 2023 में स्वीकृत किया गया।

लगभग 50 किलोमीटर लम्बाई की यह परियोजना झज्जर जिला के बादली से आरम्भ होगी और मेवात के गांव खोर बसई में सम्पन्न होगी। इस परियोजना पर पावर हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से गुरूग्राम, मानेसर व मेवात के लोगों के लिए स्वर्णिम युग की शुरूआत होगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जनसंपर्क अभियान के दौरान करनाल के लोगों से सीधा संवाद

(दिनांक 03.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल जन संपर्क अभियान के तहत वार्ड–4 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा जिनकी गलियां 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं और मुख्य रास्ते 6 मीटर से ज्यादा चौड़े हैं। इसके साथ–साथ ऐसी सभी कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का खाका तैयार कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक नगर परिषद और निगम कार्यालय में दो कर्मचारियों को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को इधर–उधर न भटकना पड़े। प्रदेश सरकार हर परिवार का सर्वे कराकर आंकड़ा जुटा रही है कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग

बेरोजगार हैं, घर में कितने बुजुर्ग हैं, सारा सर्वे कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी तरह की योजनाएं सिरे चढ़ाई जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीपीपी के माध्यम से साढ़े बारह लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। जो राशन कार्ड वैद्य हैं और गलत तरीके से कटे हैं उनको दोबारा उसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा।

परिवार पहचान पत्र से लेकर राशन कार्ड कट जाने तक की सभी गलतियां ठीक की जाएंगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम हैं, ऐसे परिवारों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ–साथ चिरायु हरियाणा योजना को लागू किया है ताकि गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला की सभी चौपालों, सभी सामुदायिक केंद्रों व सभी धर्मशालाओं का सर्वे करवाकर इनकी लिस्ट तैयार

साप्ताहिक सूचना पत्र

करें ताकि इनमें मरम्मत आदि का कार्य, अगर जरूरत है तो कराया जा सके या नया बनवाया जा सके।

इसी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करनाल के वार्ड 14 में लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी ओर से आई समस्याओं का समाधान करते हुए कहा कि बरसात के मौसम से पहले पूरे करनाल शहर की जल निकासी को लेकर सर्वे कराया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने निगमायुक्त को सभी इंजीनियरों की टीम गठित कर जल्द से जल्द सर्वे कराने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि जिन जिन कालोनियों में जलभराव की समस्या है उन सभी की लिस्ट तैयार करें और सभी इंजीनियर की टीम बनाकर सर्वे करवाया जाए कि किस कॉलोनी का पानी का फ्लो किस ओर है और वहां से जल निकासी की समस्या को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को बरसात से पहले पानी, सीवरेज, नालियां, जल

निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने तथा इन पर शीघ्रातिशीध्र काम शुरू के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की मांग पर तुरंत प्रभाव से क्षेत्र के लोगों के लिए सीएससी खोलने के भी निर्देश दिए ताकि लोग अपनी योजनाओं के आवेदन के लिए दूर न जाएं और उन्हें यह सुविधा वही नजदीक मिल जाए।

सरकारी नौकरियों में योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं जिससे नौकरियों में पारदर्शिता आई है। गरीब परिवार के व्यक्ति को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के साथ चिरायु हरियाणा योजना चलाई है।

उन्होंने कहा कि वार्ड 14 के 765 लोगों ने अपने आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवाए हैं और उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज भी कराया है। उन्होंने सभी से अपील की कि अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बनवा लें। इसी के आधार पर सभी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को जरूरी किया गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों से सीधा संवाद

(दिनांक 03.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने साप्ताहिक कार्यक्रम ब्ड `म विशेष चर्चा में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालकों से सीधा संवाद कर कहा कि पिछले साढ़े 8 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई–गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने भी गति पकड़ी है और पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप आज प्रशासन स्मार्ट (सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पांसिबल, ट्रांसपेरेंट) बना है। संवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने

सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी तो कुछ सीएससी संचालकों ने कहा कि कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है, जिससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों

साप्ताहिक सूचना पत्र

को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा, सीएससी संचालकों ने 60 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों की आयु सत्यापन का विषय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। इस पर उन्होंने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु की सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है और 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्दी शुरू करेगी।

उन्होंने कहा प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग साढ़े 500 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। प्रदेश में लगभग 13 हजार सक्रिय सामान्य सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की 12,938 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनसे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है, वहीं नागरिकों को अपने घर के नजदीक ही सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुई हैं। वित्त वर्ष 2022—23 में सीएससी के माध्यम से 1 करोड़ 72 लाख 39 हजार ट्रांजेक्शन हुई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था और कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। डिजिटल इंडिया विज़न को सफल बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हरियाणा सरकार जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर का काफी सहयोग मिला है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि पेपरलैस मोड में सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रोनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम समय में लोगों को मिलें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास

(दिनांक 03.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की करनाल जिला में करीब 1177 लाख रूपये की लागत से तैयार होने वाली 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास करके एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने निसिंग

ब्लॉक के गांव बालू में 86.89 लाख रूपये की लागत से पृथ्वी तीर्थ, गांव ओंगद में 112.11 लाख रूपये की लागत से रघुवेन्द्र दशरथ तीर्थ, निसिंग ग्रामीण में 159.31 लाख रूपये की लागत से मिश्रक तीर्थ, असंध में 40 लाख रूपये की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ, गांव अजंनथली में 229.77 लाख रूपये की लागत से अजंनी तीर्थ, गांव पतनपुरी में 231. 29 लाख रूपये की लागत से प्रोक्षांत तीर्थ, गांव सीतामाई में 134.52 लाख रूपये की लागत से वेदवती तीर्थ तथा गांव बस्तली में 183. 06 लाख रूपये की लागत से व्यास स्थल तीर्थ के कार्य का शिलान्यास किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता की भलाई के लिए गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि पहले कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरूक्षेत्र जिला के तीर्थो का ही देखभाल करता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी

है, कुरूक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने लगी, तब से लेकर धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ के अंतर्गत 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थो के महत्व को समझते हुए कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्वार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तीर्थ परिक्रमा को विकसित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है ताकि लोगों की आस्था के केन्द्र तीर्थो पर गांव के लोगों के साथ–साथ बाहर के लोग भी दर्शन के लिए आए, इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

प्रदेशवासियों को संत कबीरदास जयंती की दी शुभकामनाएं

(दिनांक 04.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत कबीरदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और प्रदेशवासियों को संत कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं दी। संत कबीरदास जी की शिक्षाएं और विचार समाज में सर्वधर्म समभाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं। संत कबीरदास के दोहे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान का उल्लेख करते हुए कहा कि संत कबीर जी की शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। हरियाणा एक–हरियाणवी एक के भाव से जाति–पाति से ऊपर उठकर प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समस्त जीवन समाज कल्याण को समर्पित किया है। युवा अवस्था से ही अपने परिवार की बजाए समाज की भलाई के लिए कार्य करना शुरू किया और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी निरंतर जन सेवा के अपने लक्ष्य को निभा रहे है। इतना ही नहीं, अपनी सादगी का परिचय देते हुए संत–महापुरुषों का सम्मान करते हुए श्री मनोहर लाल ने एक नई पहल शुरू कर मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर रख दिया है।